प्र<del>ेप</del>्नक,

सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन। ा में,

सेवा में, जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 2 5सितम्बर, 2009

विशय:—आर0एल0एस0 मैमोरियल ट्रस्ट काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर को महाविद्यालय की स्थापना हेतु कुल 1.00 है0 भूमि क्रय की अनुमित प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1196/सात—स0भु030/09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आर0एल0एस0 मैमोरियल ट्रस्ट काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर को महाविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम किशनपुर, तहसील जसपुर जिला ऊधमसिंहनगर में कुल 1.00 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्या—543िम0 रकबा 0.616 है0 एवं खसरा संख्या—543िम0 रकबा 0.606 है0 के अधीन क्रय करने की अनुमति निम्निखित शर्ती/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

- 1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।
- 2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि. बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3— केता द्वारा क्य की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के किक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बी०ए०/बी०एड० पाठ्यक्रम) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होंगें।
- 4— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति / जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति / जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमित प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भरतामी असंक्रमणीय अधिकार बाने अस्ति।

- 6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7— संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मात्र शिक्षण कार्यो (महाविद्यालय) हेतु किया जायेगा तथा इससे भिन्न भू—उपयोग किये जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी जायेगी / स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 8— किसी दंशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमित नहीं होगी एवं सार्वजिनक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो। इसके लिए भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 9— भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 10— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों / संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ / स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी ।
- 11— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू—उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 12— उपरोक्त शर्तो / प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुमार्ष कुमार) प्रमुख सचिव।

पु0प0सं0 127 4/ सम्दिनांकित 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4— अध्यक्ष, आर0एल0एस0 मैमोरियल ट्रस्ट, 312 टीचर्स कॉलोनी सुदामापुरी, काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर।
- 5— निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड संचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,